International Audit of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

2709. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Internal audit and A.G.C.R. do conduct on the accounts of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi every year;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that value and quantity of items in Stock Register never tally with the annual physical Stock verification;

(d) if so, the details thereof; and

(e) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO & RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P.J. KURIEN): (a) and (b) Audits are undertaken in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi every year and there is no report about bungling of funds due to non-maintenance of stock register. After physical verification stock lists are prepared in respect of godown, emporium and all branches.

(c) and (d) Due to heavy rush of customers, the counter slaesmen are not able to maintain the full particulars of the items which were sold to the customers, hence Bhavan finds it difficult to maintain the itemwise and varietywise Stock Registers. There are over 1350 varieties of Khadi and Village Industry articles stocked in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi.

(e) Instructions have been issued to Khadi and Village Industries Commission Bombay to take the appropriate action for settling the audit paras.

उत्तर प्रदेश में बंद पड़े मझौले/लघु उद्योग

2710. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में बन्द पड़े मझौले और लघु उद्योगों के नाम क्या-क्या हैं और वे कहां कहां पर स्थित हैं;

(ख) इन उद्योगों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा किए गए निवेशों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते हैं। मार्च 1991 के अन्त तक भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में गैर लघु क्षेत्रों में 68 रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एकक, जिनपर 154.49 करोड़ रु० का बैंक ऋण है, बन्द बताये गये थे। रुग्ण लघु एककों के संबंध में ऐसे आंकड़े केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते।

(ख) केन्द्र द्वारा ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ग) संभावित जो व्यक्षप समझे गये रुग्ण तथा कमजोर एककों के बारे में पुनर्वास पैकेज तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी निदेश जारी किए गये हैं। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की विद्यमान देय राशि चरणबद्ध तरीके से अदायगी हेतु बढ़ाई गई अवधि के साथ धन देने ब्याज रियायतें, नये सावधि ऋणों की मंजूरी तथा कार्यशील पूंजी की सुविधाओं की व्यवस्था है। जहां तक गैर लघु क्षेत्र के

औद्योगिक कम्पनियों का संबंध है, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (उपबंध) अधिनियम 1985 के अधीन गठित अर्धन्यायिक निकाय, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी एफ आई आर) को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई है कि वह रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां के संबंध में निरोधात्मक, सुधारात्मक, उपचारात्मक तथा अन्य उपाय निश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सके।

अनिवासी भारतीयों द्वारा मोटर उद्योग की स्थापना

2711. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनिवासी भारतीयों ने देश में मोटर उद्योग स्थापित करने की अनुमति मांगी है परन्तु पिछले छः वर्षों से उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्तिम उत्तर कब तक दिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क), नहीं। मोटरीकृत चार-पहिया वाहनों और इंजनों के निर्माण के लिए जिला अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश में एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु 1986 में यू०एस०ए० से एक अनिवासी भारतीय डॉ वी०एस०आर० मूर्ति से केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। किन्तु यात्री कार उद्योग में पर्याप्त क्षमता पहले से ही सृजित होने और विदेशी मुद्रा संबंधी बाधाओं को देखते हुए यह आवेदन नामंजूर कर दिया गया था। पार्टी को अन्तिम अस्वीकृति पत्र 16.10.1989 को जारी किया गया था।

(ख) और (क) प्रश्न नहीं उठता।

Foreign Investment in Private Public Sector

2712. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the names of major projects involving foreign investment or without involving foreign investment in the private as well as in public sector pending with Government and the number of them cleared by Government in the current year;

(b) what is the foreign investment involved and what are the details of cleared projects;

(c) whether some power pojects are still pending; and

(d) if so, the action proposed to be taken to clear them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c); The details of proposals for foreign collaboration both from private and public sectors cleared during the current year till 31st October, 1992 are as under:—

Year	Total No. of foreign collaborations cleared	No. of foreign collaboration proposals involving foreign investment cleared	Total amount of foreign investment involved
1992 (Oct.)	1242	538	3266.30 crores

Some of the projects pending for consideration of the Govt. are in sectors like telecommunications, power sector, petroleum products etc.

(d) The proposals are generally cleared within a period of 45 days or so unless their considerations are pending for appropriate policy decision.